

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी

328. श्री श्रीकाश लाल बेरवा :

श्री श्रीहृदय सिंह :

श्री जे० आर० पटेल :

श्री राम सिंह धायरवाल :

क्या सिचार्ज और विद्युत बोर्ड यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1967 के अंतिम सप्ताह में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के 18,000 कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर छुट्टी ली;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) जिन राज्यों में इसके परिणाम-स्वरूप विद्युत सम्भरण में बाधा पड़ी, उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

सिचार्ज व विद्युत बोर्ड (शा० कु० ला० राब): (क) पंजाब राज्य विजली बोर्ड के अधिकांश नान-गजेटेड कर्मचारियों ने 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आकस्मिक छुट्टी के लिये प्रार्थना पत्र दिए थे। 29 अप्रैल को उन्होंने अपना आन्दोलन बन्द कर दिया था और वे 26 अप्रैल से लेकर तब तक अपनी ड्यूटी पर नहीं आए।

(ख) संगठित पंजाब राज्य विजली बोर्ड, इसके विघटित होने से पूर्व, के कर्मचारियों के बेलन-मानों में पुनरोत्थन की मांग पर और देने के लिये।

(घ) जम्मू और काश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के राजर तथा कच्ची-गड़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र।

(घ) और (ङ). थापलान में काम आने वाले व्यक्तियों के प्रबन्ध के लिये कुछ संबोद्धत किए जा रहे थे किन्तु इस प्रस्ताव को कार्यान्वयन करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि आन्दोलन 29 अप्रैल को रगत को समाप्त हो गया था।

Excise Collectorate

329. Shri Sradhakar Supakar:
Shri Chintamani Panigrahi:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether in view of the rise in the Central Excise Revenue and workload, some new excise Collectorates are to be established; and

(b) if so, the location of the new Collectorates?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Government are not considering just now any proposal for setting up new Central Excise Collectorates.

(b) Does not arise.

Land Prices in Delhi

330. Shri Liladhar Kotaki: Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether Government propose to review Delhi's housing policy to bring down land prices and step up building activity; and

(b) whether any special change is likely to be made in the policy as far as the employees in Government service are concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Certain proposals for liberalising the Scheme of Large Scale Acquisition, Development and Disposal of Land in Delhi, are under consideration. The housing problem of Delhi is also under constant review with a view to accelerating the pace of construction of